eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 10, October 2024

भारत में पर्यावरण संबंधी मुद्दे और आंदोलन का एक ऐतिहासिक अध्ययन

सुनीता निरंकारी[1], डॉ0 नानक चंद[2]
[1]रिसर्च स्कॉलर
[2]सुपरवाइजर, (असिस्टेंट प्रोफेसर) कला विभाग मंगलायतन विश्वविद्यालय बेसवाँ अलीगढ उ0प्र0

Received: 24 Oct 2024 Accepted & Reviewed: 25 Oct 2024, Published : 31 Oct 2024

Abstract

वर्तमान अध्ययन कोल्हापुर जिले में स्थानीय पर्यावरण आंदोलनों पर केंद्रित है। इसलिए, सैद्धांतिक वैचारिक पृष्ठभूमि के एक भाग के रूप में, वर्तमान अध्याय सामाजिक आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, पुराने और नए सामाजिक आंदोलनों और भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलनों के संक्षिप्त विवरण जैसी अवधारणाओं से संबंधित है। खंड–I 1, सामाजिक आंदोलन की अवधारणा विद्वानों के पास, अधिक सामान्य अर्थ में, सामाजिक आंदोलन की संरचना के बारे में अलग–अलग धारणाएँ हैं। सामाजिक आंदोलन शब्द पहली बार उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में प्रयोग में आया, इसका एक अधिक विशिष्ट अर्थ था। सामाजिक आंदोलन का अर्थ था नए औद्योगिक श्रमिक वर्ग का आंदोलन, जिसमें समाजवादी, साम्यवादी और अराजकतावादी प्रवृत्तियाँ थीं सामाजिक आंदोलन या अन्य पश्चिमी भाषाओं में इसके समतुल्य शब्द का उपयोग कुछ सामाजिक संस्थाओं में बदलाव लाने या एक पूरी तरह से नई व्यवस्था बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की एक विस्तृत विविधता को दर्शाने के लिए किया जा रहा है।

आंदोलन समाज में होते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उन सभी पर सामाजिक आंदोलन शब्द लागू करना स्वीकार्य होगा इस संदर्भ में सिल्स, डेविड ने नोट किया कि सामाजिक आंदोलन एक विशिष्ट प्रकार के संगठित कार्रवाई समूह हैं वे लंबे समय तक चलते हैं और भीड़, जनसमूह और भीड़ की तुलना में अधिक एकीकृत होते हैं और फिर भी राजनीतिक क्लबों और अन्य संघों की तरह संगठित नहीं होते हैं। हालाँकि, एक सामाजिक आंदोलन में संगठित समूह शामिल हो सकते हैं, बिना किसी औपचारिक संगठन के (उदाहरण के लिए, श्रमिक आंदोलन, जिसमें ट्रेड यूनियन, राजनीतिक दल, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ और कई अन्य संगठन शामिल हैं) समूह चेतना, यानी समूह के सदस्यों के बीच अपनेपन और एकजुटता की भावना, एक सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक है, हालाँकि अनुभवजन्य रूप से यह विभिन्न डिग्री में होता है।

मुख्य शब्द– पर्यावरणीय चेतना, सामाजिक आंदोलन, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, पर्यावरणीय आंदोलन, स्थानीय पर्यावरण आंदोलन।

Introduction

पर्यावरण की यह चेतना सक्रिय भागीदारी से उत्पन्न होती है और विभिन्न समाज–मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को ग्रहण कर सकती है। इस मानदंड से सामाजिक आंदोलनों को श्सामाजिक प्रवृत्तियों से अलग किया जाता है, जिन्हें अक्सर आंदोलनों के रूप में संदर्भित किया जाता है और वे कई व्यक्तियों के समान लेकिन असमन्वित कार्यों का परिणाम होते हैं, उदाहरण के लिए, उपनगरीय आंदोलन, सनक और

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 10, October 2024

फैशन। सामाजिक आंदोलनों की परिभाषाएं जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र विश्वकोश में परिभाषित किया गया है, एक सामाजिक आंदोलन गैर–संस्थागत साधनों द्वारा मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तनों को प्रभावित करने या विरोध करने के लिए साझा विश्वास से एकजुट कई लोगों द्वारा एक संगठित प्रयास है। सामाजिक आंदोलन का अंतिम उद्देश्य यह है कि इसके सदस्य समाज की बेहतरी के रूप में क्या देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश ने सामाजिक आंदोलनों को सामाजिक व्यवस्था के कुछ पहलू में बदलाव की सामाजिक रूप से साझा मांगों के रूप में परिभाषित किया है मार्टेल ने सामाजिक आंदोलन को "स्थापित संस्थाओं के बाहर सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से एक सामान्य हित या लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक सामूहिक प्रयास" के रूप में परिभाषित किया है। डायनी के अनुसार "सामाजिक आंदोलन व्यक्तियों और संगठनों के बीच अनौपचारिक बातचीत का एक नेटवर्क है जो एक साझा पहचान के आधार पर सामूहिक कार्रवाई में संलग्न होते हैं संगठन औपचारिक, अनौपचारिक, संस्थागत या गैर–संस्थागत को केवल तभी आंदोलन का हिस्सा माना जा सकता है जब वे अन्य संगठनों से जुड़े हों जो समान मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई में संलग्न हों" सामाजिक आंदोलनों के कायर्रू सिल्स, डेविड एल. ने सामाजिक आंदोलनों के निम्नलिखित दो कार्यों को नोट किया। आंदोलन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा के लिए और आंदोलन के विचारों को अंततः प्रमुख जनमत में शामिल करने के माध्यम से जनमत के निर्माण में योगदान देता है और यह उन नेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है जो राजनीतिक अभिजात वर्ग का हिस्सा बन जाते हैं और अंततः प्रमुख राजनेताओं के पदों तक पहुंच सकते हैं। यह दोनों कार्य उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां आंदोलन, सामाजिक व्यवस्था को बदलने या संशोधित करने के बाद, इसका हिस्सा बन जाता है, आंदोलन का जीवन चक्र समाप्त हो जाता है।

यह एक संस्था बन गया है, पर्यावरण आंदोलन की अवधारणा पर्यावरण आंदोलन एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है जिसमें व्यक्तियों, समूहों और गठबंधनों की एक श्रृंखला शामिल होती है जो पर्यावरण संरक्षण में एक समान रुचि को समझते हैं और पर्यावरण नीतियों और प्रथाओं में बदलाव लाने के लिए कार्य करते हैं। बताते हैं कि पर्यावरण आंदोलन भी सामाजिक आंदोलनों का एक उदाहरण हैं। सामाजिक आंदोलनों का उद्भव और विकास कारकों के तीन व्यापक सेटों की गतिशील बातचीत पर निर्भर करता है। सबसे पहले, सामाजिक आंदोलन व्यापक राजनीतिक बाधाओं और राष्ट्रीय संदर्भ के लिए अद्वितीय अवसरों द्वारा आकार लेते हैं जिसमें वे उभरते हैं। इन बाधाओं और अवसरों में एक राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली की संस्थागत संरचना और अनौपचारिक शक्ति संबंध शामिल हैं, जिसमें संस्थागत राजनीतिक प्रणाली का सापेक्ष खुलापन या बंद होना, राजनीति को रेखांकित करने वाले अभिजात वर्ग के गठबंधन की स्थिरता, किसी विशेष सामाजिक आंदोलन के लिए अभिजात वर्ग के सहयोगियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति और दमन के लिए राज्य की क्षमता और प्रवृत्ति शामिल है। दूसरा, लोगों को सामूहिक कार्रवाई में जुटाने और एक सामाजिक आंदोलन को बनाए रखने के लिए संगठनात्मक संसाधन, अनौपचारिक और साथ ही औपचारिक, उपलब्ध होने चाहिए। संसाधनों में पहले से मौजूद संगठन, जैसे अनौपचारिक नेटवर्क, स्वैच्छिक संघ और धार्मिक समूह, साथ ही आंदोलन शुरू किए गए संगठन शामिल हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंदोलन को विभिन्न संगठनात्मक रूपों की आवश्यकता हो सकती है। किसी दिए गए समाज की संगठनात्मक संस्कृति सामाजिक आंदोलन के रूपों को भी प्रभावित कर सकती है। तीसरा, व्याख्या, आरोपण और सामाजिक निर्माण की सामूहिक प्रक्रिया सामूहिक कार्रवाई को अर्थ और मूल्य प्रदान करती है। अपनी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 10, October 2024

स्थिति में साझा अर्थ और परिभाषाएँ लाकर, जो लोग अपने जीवन के किसी पहलू से व्यथित महसूस करते हैं, वे अधिक आशावादी हो सकते हैं कि, सामूहिक रूप से कार्य करके, वे अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। उचित रूपरेखा के बिना, यह बेहद असंभव है कि लोग ऐसा करने के अवसर मिलने पर भी जुटेंगे पर्यावरण आंदोलनों को बहुत ही विविध और जटिल माना जाता है, उनके संगठनात्मक रूप अत्यधिक संगठित और औपचारिक रूप से संस्थागत से लेकर मौलिक रूप से अनौपचारिक तक होते हैं, उनकी गतिविधियों का स्थानिक दायरा स्थानीय से लेकर लगभग वैश्विक तक होता है, उनकी चिंताओं की प्रकृति एकल मुद्दे से लेकर वैश्विक पर्यावरणीय चिंताओं के पूरे दायरे तक होती है। इस तरह की समावेशी अवधारणा पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बीच इस शब्द के उपयोग के अनुरूप है और हमें उन कई स्तरों और रूपों के बीच संबंधों पर विचार करने में सक्षम बनाती है जिन्हें कार्यकर्ता श्पर्यावरण आंदोलन कहते हैं और इनके अनुसार सामूहिक कार्रवाई के तीन स्तर हैं स्थानीय जमीनी स्तर का आंदोलन स्तरय सामाजिक आंदोलन स्तरय और विरोध का चक्र, एक स्थानीय जमीनी स्तर का पर्यावरण आंदोलन (LGEM) एक भौगोलिक रूप से निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रदूषण के एक विशेष उदाहरण से लड़ने वाला आंदोलन है। स्थानीय जमीनी स्तर के पर्यावरण आंदोलनों के लक्ष्यों की एक सीमित सीमा होती है जो विशिष्ट प्रदूषण समस्याओं से जुड़ी होती है। सामाजिक आंदोलन एक व्यापक संघर्ष है जिसमें औपचारिक संगठन या शिथिल रूप से संबद्ध नेटवर्क का संघ शामिल होता है। सामाजिक आंदोलनों के पास मौलिक सामाजिक और राजनीतिक सुधार पर निर्देशित लक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। अंत में, विरोध का एक चक्र समाज के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और क्षेत्रों में फैले कई सामाजिक आंदोलनों को शामिल करते हुए तीव्र विरोध की एक विशिष्ट अवधि है। आंदोलन गतिविधि के प्रत्येक स्तर की पहचान उस राजनीतिक वातावरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें एक स्थानीय जमीनी स्तर का पर्यावरण आंदोलन संचालित होता है, पुराने और नए सामाजिक आंदोलन विद्वान पुराने और नए सामाजिक आंदोलनों के बीच अंतर करते हैं। मुख्य आधार जिस पर पुराने और नए सामाजिक आंदोलनों को अक्सर अलग किया जाता है। पुराने सामाजिक आंदोलन राजनीति में, राजनीतिक दलों में स्थित होते हैं, जबकि नए सामाजिक आंदोलन पारंपरिक राजनीतिक संस्थाओं के बाहर स्वायत्त आंदोलन होते हैं।

उद्देश्य पुराने सामाजिक आंदोलनों का उद्देश्य राजनीतिक समुदाय में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, विधायी राजनीतिक सुधार और नागरिकता से जुड़े अधिकारों को सुरक्षित करना है, जबकि नए सामाजिक आंदोलन राज्य के माध्यम से विधायी परिवर्तन करने के बजाय नागरिक समाज को राजनीतिक शक्ति के खिलाफ बचाना और नागरिक समाज में संस्कृति और जीवन शैली को फिर से परिभाषित करना चाहते हैं। संगठन पुराने सामाजिक आंदोलन संगठनों की विशेषता संगठन के औपचारिक और पदानुक्रमित आंतरिक रूपों से होती है, जबकि नए सामाजिक आंदोलन अधिकार के ढांचे के बजाय अनौपचारिक या असंरचित संगठन को प्राथमिकता देते हैं। परिवर्तन का माध्यमरू पुराने सामाजिक आंदोलन राजनीतिक संस्थाओं की ओर उन्मुख होते हैं जिनके माध्यम से परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है। नए सामाजिक आंदोलन प्रत्यक्ष कार्रवाई के नए और अधिक अभिनव रूपों को अपनाते हैं। वे राजनीतिक तंत्र के माध्यम से परिवर्तन करने के बजाय संस्कृति में अर्थ और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की नई पुनर्परिभाषा पर काम करते हैं। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में छात्र आंदोलनों से जो नए सामाजिक आंदोलन उभरे, वे पर्यावरण आंदोलन थे जिनका राजनीति पर सबसे अधिक स्थायी प्रभाव रहा और जो अपनी गतिविधियों के व्यावसायीकरण और

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 10, October 2024

नीति–निर्माताओं तक उनकी पहुंच के नियमितीकरण दोनों के संदर्भ में सबसे व्यापक संस्थागतकरण से गुजरे हैं नेपाल, पदम का तर्क है कि, भारत में नए सामाजिक आंदोलन भारत की राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित विपक्षी ताकतों, विशेष रूप से वाम, और विशेष रूप से नक्सल आंदोलन के टूटने के बाद, राष्ट्रीय परियोजना की विफलता और एक–पक्षीय प्रभुत्व की विशेषता वाले दौर में अधीनस्थ, सीमांत समूहों की गतिविधि को दिशा देने और संगठन प्रदान करने में विफल रहे ने बताया है पहला, वामपंथी दृष्टिकोण जो पर्यावरण आंदोलन को वर्ग संघर्ष के विस्थापित रूप के रूप में देखता है, और इसकी जड़ें वर्ग–विभाजित भारतीय समाज में हैं। दूसरा दृष्टिकोण नए सामाजिक आंदोलनों को केंद्रीकृत राज्य के खिलाफ संघर्ष के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण हालांकि आंदोलन को वर्ग शोषण के उपोत्पाद के रूप में स्वीकार करता है, फिर भी यह नए सामाजिक आंदोलनों की विशेष, मुद्दा–विशिष्ट प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करता है। पर्यावरण आंदोलन सहित एक नए सामाजिक आंदोलन का दोहरा पहलू होता है सामान्य पहलू इस अर्थ में कि यह मुख्य रूप से आधुनिक राज्य की सर्वशक्तिमान प्रकृति के खिलाफ एक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका शिकार कुछ खास वर्ग के लोग होते हैं, और एक विशेष सामाजिक श्रेणी से संबंधित एक विशिष्ट, स्थानीयकृत मुद्दे को संबोधित करने का एक विशेष पहलू जैसे महिलाओं का मुद्दा, एक पर्यावरण मुद्दा, एक आदिवासी आबादी का अपने प्राकृतिक आवास से विस्थापन का मुद्दा आदि। क्या पर्यावरण आंदोलन श्पुरानेश हैं या श्नएश? पर्यावरण आंदोलनों की विशेषता पुराने और नए दोनों सामाजिक आंदोलनों की विशेषताएं हैं, जिन्हें मार्टेल, ल्यूक द्वारा आलोचनात्मक रूप से सामने लाया गया है। पर्यावरण आंदोलनों की विशेषताएं जो उन्हें नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में फिट करती हैं, उनमें शामिल हैं कुछ पर्यावरण समूह अपने आंदोलन में संगठन के गैर–पदानुक्रमित रूपों को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं, नेताओं के पदानुक्रम की भूमिका को कम करते हैं। कई पर्यावरण समूह जमीनी स्तर पर आधारित विकेन्द्रित भागीदारी को प्राथमिकता देते हैं। कई लोग यह तर्क देते रहते हैं कि हमारे अधिग्रहण मूल्य प्रणालियों और जीवन जीने के तरीकों में व्यापक बदलाव के बिना राजनीतिक कानून अपर्याप्त हैं। इसमें राज्य के माध्यम से नए कानूनों को पारित करने के बजाय नागरिक समाज में चेतना के तरीकों में बदलाव शामिल है। पर्यावरण आंदोलनों में पुराने आंदोलनों की कुछ विशेषताओं में शामिल हैं। कई पर्यावरण संगठन राजनेताओं को गिरावट को ठीक करने के लिए काम करने के लिए चिंतित हैं। कुछ विद्वान पर्यावरण आंदोलनों को विभिन्न लेबलों के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं जैसे 'आदिवासी या किसान आंदोलन' या 'नए सामाजिक आंदोलन', कुछ तो उन्हें 'मध्यम वर्ग' या 'अभिजात्य आंदोलन' भी कहते हैं ।

, भारत में पर्यावरण आंदोलनों की उत्पत्ति, उनके कारणों और भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलनों का संक्षिप्त वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। भारत में पर्यावरण आंदोलनों की उत्पत्ति भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिंता की उत्पत्ति, ष्बीसवीं सदी की शुरुआत में देखी जा सकती है जब लोगों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान वन संसाधनों के व्यावसायीकरण का विरोध किया था फिर, वह कहते हैं कि, यह केवल 1970 के दशक में था कि राज्य–एकाकी विकास प्रक्रिया के पारिस्थितिक प्रभाव के बारे में एक सुसंगत और अपेक्षाकृत संगठित जागरूकता विकसित होनी शुरू हुई, जो प्राकृतिक संसाधनों की सीमित प्रकृति की पूरी तरह से समझ में विकसित हुई और प्राकृतिक संसाधनों की कमी को रोका जा सका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पर्यावरणीय संकट की बढ़ती प्रमुखता चार महत्वपूर्ण घटनाओं से सामने आई। तीसरा, ब्रून्डलैंड आयोग की रिपोर्ट 'हमारा साझा भविष्य' का विमोचन। चौथी घटना थी 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में गुहा,

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 10, October 2024

रामचंद्र ने 1973 में देश में घटित तीन घटनाओं को सूचीबद्ध किया है, जिसने भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर बहस को सुविधाजनक बनाया सबसे पहले, अप्रैल में, भारत सरकार ने देश के राष्ट्रीय पशु की रक्षा के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करने की घोषणा की विश्व वन्यजीव कोष और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रोत्साहित और मदद प्राप्त भारतीय संरक्षणवादियों ने लुप्तप्राय वन्यजीवों की रक्षा के लिए पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का एक नेटवर्क बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने देश में भूमि क्षरण, जलभराव और अन्य प्रकार के भूमि क्षरण की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस लेख के माध्यम से लेखक ने इस संबंध में राज्य द्वारा एक प्रभावी नीति तैयार करने और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त भूमि उपयोग पैटर्न की निगरानी और प्रबंधन के लिए सरकारी विभागों के गठन का आह्वान किया। यह पर्यावरणीय क्षरण से संबंधित पहली आधिकारिक चिंता को दर्शाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उसी वर्ष पर्यावरण संरक्षण और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई और पांच साल बाद एक पूर्ण पर्यावरण और वन मंत्रालय बनाया गया। तीसरा, 27 मार्च, 1973 को एक सुदूर हिमालयी गांव मंडल में किसानों के एक समूह ने पेड़ों को पकड़कर लकड़हारों के एक समूह को पेड़ों की कटाई करने से रोक दिया।

इस घटना ने 1970 के दशक में इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिसे सामूहिक रूप से चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन ने पारिस्थितिकी, समानता और सामाजिक न्याय से संबंधित बुनियादी सवाल उठाए और पूरे देश में जीवंत बहस और कार्रवाई को बढ़ावा दिया। इस प्रकार, भारत में पर्यावरण संबंधी बहस का उदय विशेष रूप से 1970 और 1980 के दशक के बाद बड़ी संख्या में पर्यावरण आंदोलन उभरे हैं। इस संदर्भ में साहू, गीतंजय ने कहा कि भारत में पिछले तीन से चार दशकों में पर्यावरण आंदोलन तेजी से बढ़ा है। इसने तीन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जैसे पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन लाने के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना,, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के प्रतिकूल विकास परियोजनाओं का विरोध करना और ऐसे मॉडल परियोजनाओं का आयोजन करना जो गैर–नौकरशाही और भागीदारी, समुदाय–आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणालियों की ओर आगे का रास्ता दिखाते हैं जैसा कि रेड्डी, रत्ना ने बताया है। भारत में विशेष रूप से 1970 के दशक के बाद हालांकि, समकालीन आंदोलनों में से कुछ ने पूर्वव्यापी रूप से पारिस्थितिक या पर्यावरण आंदोलनों का दर्जा हासिल कर लिया क्योंकि इन आंदोलनों ने बुनियादी अस्तित्व की जरूरतों से पारिस्थितिक चिंताओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है"। भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों के उद्भव के कारणरू भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों के उद्भव के प्रमुख कारणों की चर्चा शर्मा, अविराम ने की है जिसमें निम्नलिखित कारण शामिल हैं प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, पप) सरकार की झूठी विकासात्मक नीतियां, सामाजिक–आर्थिक कारण पर्यावरणीय गिरावट विनाश और, पर्यावरण जागरूकता और मीडिया का प्रसार। भारत में प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारत में विशेषकर 1970 के दशक के बाद बड़ी संख्या में पर्यावरणीय आंदोलन उभरे हैं

भारत में पर्यावरण आंदोलन, अमेरिकन ज्योग्राफिकल सोसायटी, खंड 84, संख्या 1, भारत में कुछ सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलनों का संक्षेप में विवरण नीचे दिया गया है बिश्नोई आंदोलन इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी ने किया था जिसमें लगभग 363 लोगों ने अपने जंगलों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 10, October 2024

की आहुति दी थी। यह आंदोलन अपने आप में पेड़ों की सुरक्षा के लिए उन्हें गले लगाने या उनका आलिंगन करने की रणनीति विकसित करने वाला अपनी तरह का पहला आंदोलन था । चिपको आंदोलन चिपको भारत में दुनिया के प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलनों में से एक है। चिपको आंदोलन ने मध्य पश्चिमी हिमालय में अलकनंदा जलग्रहण क्षेत्र की पर्यावरणीय समस्याओं पर विश्व का ध्यान केंद्रित किया जैसा कि रेड्डी ने लिखा है कि, बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में औपनिवेशिक वन नीति के विरोध में कई संघर्ष आयोजित किए गए थे। पेड़ों की कटाई और उन्हें पहाड़ियों से नीचे लुढ़काने से ऊपरी मिट्टी ढीली हो गई जो बारिश के दौरान और अधिक कट गई। इन सबके परिणाम स्वरूप जुलाई 1970 में अलकनंदा में विनाशकारी बाढ़ आई, जिसने ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में तबाही मचा दी। यहीं पर दशोली ग्राम सरराज्य मंडल (DGSM), गोपेश्वर, उत्तराखंड में सामाजिक कार्यों में लगा हुआ था और 1970 के दशक की बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में आगे आया था। मंडल के स्वयंसेवकों को एहसास हुआ कि जंगल और जमीन तथा जंगल और मनुष्य एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। फिर उन्होंने लोगों को पहाड़ी ढलानों में वनों की कटाई के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करना शुरू किया और धीरे–धीरे उन्होंने खुद को एक आंदोलन में बदल लिया रेड्डी लिखते हैं कि, "1973 की शुरुआत में वन विभाग ने राख के पेड़ों को एक निजी कंपनी को आवंटित कर दिया था। इस घटना ने दशोली ग्राम स्वराज्य संघ (DGSS) नामक एक स्थानीय सहकारी संगठन को लकड़ी के ट्रकों के सामने लेटने और राल और लकड़ी के डिपो को जलाने के माध्यम से इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया, जैसा कि भारत छोड़ो आंदोलन में किया गया था अपनी सफलता के साथ, आंदोलन अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में फैल गया, और उसके बाद से यह आंदोलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है" आंदोलन का नाम, यानी 'चिपको', हिंदी के शब्द 'गले लगाना' से आया है।

ऐसा कहा जाता है कि गांववाले ठेकेदारों द्वारा पेड़ों को काटे जाने से बचाने के लिए जंगल में पेड़ों को गले लगाते, गले लगाते या उनसे चिपक जाते थे, पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए पेड़ों को 'गले लगाने' की रणनीति चंडी प्रसाद भट्ट ने 1 अप्रैल, 1973 को मंडल की एक बैठक में सोची थी। 'चिपको' नाम पेड़ों से चिपके रहने की सहमतिपूर्ण रणनीति से लिया गया था, जो एक अहिंसक प्रत्यक्ष कार्रवाई थी 1980 के दशक के अंत तक आंदोलन दो समूहों में विभाजित हो गया था, जिन्हें व्यापक जमीनी समर्थन प्राप्त था और जो भागीदारी के तरीकों की वकालत करते थे, जो स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में स्थानीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते थे। रेड्डी, रत्ना और मुकुल बताते हैं कि, चिपको आंदोलन की छह मांगें थीं– जिनमें से केवल एक पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर पूरी तरह से रोक है। अन्य मांगों में शामिल हैं, लोगों की न्यूनतम जरूरतों के आधार पर पारंपरिक अधिकारों का पुनर्गठन होना चाहिए वन से संबंधित घरेलू उद्योग विकसित किए जाने चाहिए तथा इसके लिए कच्चा माल, धन और तकनीक उपलब्ध कराई जानी चाहिएय और स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर वनरोपण में स्थानीय किस्मों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए मुकुल नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत के पर्यावरण इतिहास में सबसे लोकप्रिय आंदोलन नर्मदा नदी घाटी परियोजना के खिलाफ आंदोलन है। नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप पर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा अपने 1,312 किलोमीटर लंबे मार्ग से सुंदर वन पहाड़ियों, समृद्ध कृषि क्षेत्रों से होते हुए अरब सागर तक पहुँचती है। रेड्डी ने लिखा है किरू शुरू में यह आंदोलन मानवाधिकारों के मुद्दे पर केन्द्रित था वर्तमान में मेधा पाटकर जैसे आंदोलन के मुख्य नेता

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 10, October 2024

बांध विस्थापितों के लिए उचित पुनर्वास कार्यक्रमों की दिशा में काम कर रहे थे। राज्य द्वारा पुनर्वास कार्यक्रमों के अनुचित कार्यान्वयन के कारण, मानवाधिकार कार्यकर्ता बांध विरोधी विरोधों के मुखर वक्ता बन गए हैं। उनकी मांगों में बांध का निर्माण पूरी तरह से रोकना, विस्थापितों को पुनर्वास और पुनर्वास लाभ देना शामिल था हालाँकि, विस्थापितों (ज्यादातर आदिवासी) के जुटने और संगठित होने तथा बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा और मेधा पाटकर जैसे प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने से आंदोलन ने व्यापक सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया।

निष्कर्ष, स्वतंत्रता के बाद, सरकार ने राजस्व के लिए पेड़ों को काटना भी शुरू कर दिया और वन विभाग ने, जिसने औपनिवेशिक वन नीति को जारी रखा, आदिम उष्णकटिबंधीय जंगलों को मोनोकल्चर सागौन और नीलगिरी के बागानों में बदल दिया...बालेगड्डे गांव में युवाओं के एक समूह ने सागौन के बागान लगाने के कदमों का विरोध करते हुए वन अधिकारियों को पत्र लिखकर प्राकृतिक जंगल को साफ करना बंद करने के लिए कहा सितंबर 1983 में, जब कुल्हाड़ी चलाने वाले कलसे के जंगलों में कटाई करने आए, तो लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया और इस तरह 'अप्पिको आंदोलन' शुरू हुआ। शेठ, प्रवीण (1997) ने बताया कि, "अप्पिको आंदोलन अपने तीन गुना उद्देश्यों में सफल रहा जिसमें शामिल हैं मौजूदा वन क्षेत्र की रक्षा करना, नंगी भूमि में पेड़ों का पुनर्जनन, और, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उचित विचार के साथ वन संपदा का उपयोग करना३ अप्पिको आंदोलन ने लोगों के लिए बुनियादी जीवन स्रोतों को बचाया– बांस जैसे पेड़ जो दस्तकारी की वस्तुएं बनाने के लिए उपयोगी हैं जिन्हें वे कुछ रुपये कमाने के लिए बेच सकते थे। इसने स्थानीय लोगों द्वारा उनके उपयोग के लिए औषधीय पेड़ों को भी बचाया" इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि, "आंदोलन ने पूरे पश्चिमी घाट में ग्रामीणों के बीच वाणिज्यिक और औद्योगिक हितों द्वारा उनके जंगल के लिए उत्पन्न पारिस्थितिक खतरे के बारे में जागरूकता पैदा की, साइलेंट वैली आंदोलनरू केरल में साइलेंट वैली में 89 वर्ग किलोमीटर का समृद्ध जैविक खजाना है जो हरी–भरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय कुंवारी जंगलों के विशाल विस्तार में स्थित है। 1980 के दशक में, कुंद्रेमुख परियोजना के तहत क्रिस्टल क्लियर नदी कुंतीपुझा पर 200 मेगावाट का एक पनबिजली बांध बनाया जाना था, प्रस्तावित परियोजना पारिस्थितिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अल्मेडा, पॉल और लिंडा ब्रूस्टर स्टर्न्स (फरवरी, 1998) श्राजनीतिक अवसर और स्थानीय जमीनी स्तर के पर्यावरण आंदोलन मिनामाता का मामला, सामाजिक समस्याएँ, खंड 45, संख्या 1, पृष्ठ 37–60।
- फोर्सिथ, टिमोथी (2001) थाईलैंड में पर्यावरण संबंधी सामाजिक आंदोलन वर्ग कितना महत्वपूर्ण है एशियन जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 29, 1, पृष्ठ 35–51
- फ्रैंक, एन. मैगिल (1995) इंटरनेशनल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशियोलॉजी, खंड दो, फिट्जरॉय डियरबॉर्न (एफडी), पब्लिशर्स इंग्लैंड, लंदन, पृष्ठ 781–1527।
- गाडगिल, माधव और रामचंद्र गुहा (1998) भारत में पर्यावरण आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य की ओर, द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, खंड 59, अंक I भाग 2, पृष्ठ 450–472।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 10, October 2024

- गुहा, रामचंद्र (1988)'भारतीय पर्यावरणवाद में वैचारिक रुझान', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 23, संख्या 49, पृ. 2578–2581.
- गुहा, रामचंद्र (15–21 फरवरी, 1997) 'भारत में सामाजिक–पारिस्थितिक अनुसंधान एक स्थिति रिपोर्ट', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 32, संख्या 7, पृ. 345–352.